



Prahlad Narayan Sharma
IAS, AIR 104, CSE 2021

भारतीय अध्ययन संग्रह COMPENDIUM with NCERT (Class 9 to 12)

Coverage for UPSC IAS &
State PSC General Studies
Prelims & Main Exams

~~Sample~~

4th Edition

- एनसीईआरटी समावेश के साथ सम्पूर्ण सैद्धांतिक तथ्य
- यूपीएससी व राज्य पीएससी के विगत वर्ष के प्रश्न
- अभ्यास कार्य 1 व 2 : सामान्य तथा उच्चतर अभ्यास कार्य
- मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास तथा विगत वर्ष के प्रश्न


DISHA™
Publication Inc

DISHA Publication Inc.

A-23 FIEE Complex, Okhla Phase II

New Delhi-110020

Tel: 49842349/ 49842350

© Copyright DISHA Publication Inc.

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without prior permission of the publisher. The author and the publisher do not take any legal responsibility for any errors or misrepresentations that might have crept in.

We have tried and made our best efforts to provide accurate up-to-date information in this book.

Typeset By

DISHA DTP Team

Buying Books from Disha is always Rewarding

This time we are appreciating your writing

Creativity.

Write a review of the product you purchased on Amazon/
Flipkart

Take a screen shot / Photo of that review

Scan this QR Code →

Fill Details and submit | That's it ... Hold tight n wait.

At the end of the month, you will get a surprise gift from
Disha Publication



Scan this QR code

Write To Us At

feedback_disha@aiets.co.in

www.dishapublication.com



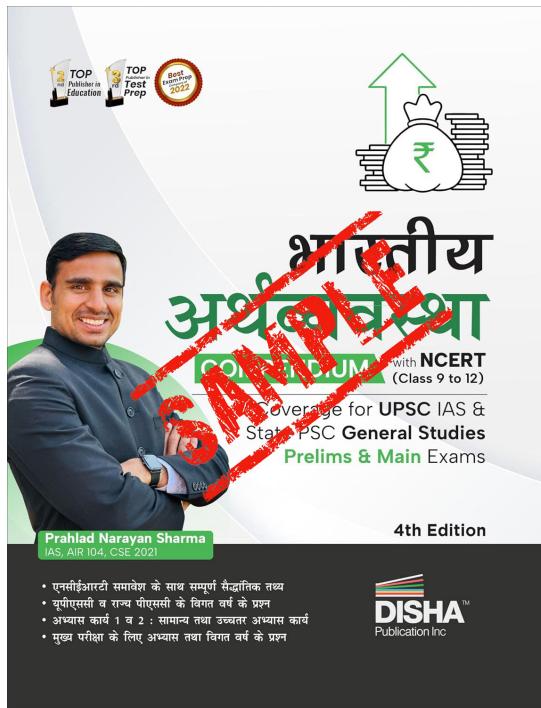
DISHATM
Publication Inc

Free Sample Contents

2. भारतीय अर्थव्यवस्था : एक परिचय 5-14

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
अर्थशास्त्र की शाखाएँ		11
विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण		11
विश्व बैंक का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था के प्रकार		11
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र		11
प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector), द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector), तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)		11
भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण		11

This sample book is prepared from the book "Bhartiya Arthvyavastha Compendium with NCERT (Class 9 to 12) coverage for UPSC IAS & State PSC Samanya Adhyayan Prelim & Main Exams 4th Edition | Civil Sewa/ Services".



ISBN - 978-9355640031

MRP- 440/-

In case you like this content, you can buy the **Physical Book or E-book** using the ISBN provided above.

The book & e-book are available on all leading online stores.

विषय-सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था : एक दृष्टि में.....1-4

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
जनसांख्यिकी (2011 की जनगणना के अनुसार)		11
कृषि उत्पादन (भारत)		11
खनिज उत्पादन व भंडार, कृषि उत्पादन (विश्व)		11
फसल उत्पादकता : भारत एवं विश्व, खनिज उत्पादन व भंडार (विश्व)		11
2018-19 में तीन सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन,		11
मुख्य पशुधन उत्पादों और मछली का उत्पादन		11

2. भारतीय अर्थव्यवस्था : एक परिचय.....5-14

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
अर्थशास्त्र की शाखाएँ		11
विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण		11
विश्व बैंक का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था के प्रकार		11
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र		11
प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector), द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector), तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)		11
भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण		11

3. राष्ट्रीय आय.....15-22

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय (National Income at Current Prices)		11
स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय (National Income at Constant Prices)		11
राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ (Concept of National Income)		12
सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP)		12
हरित सूचकांक (Green Index)	11	
पुनरावलोकन	11	

4. भारत में नियोजन23-35

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
नियोजन का उद्देश्य, भारत में निवेश का इतिहास, नियोजन के प्रकार		11
आदेशात्मक नियोजन (Imperative Planning)		11
केन्द्रीकृत नियोजन (Centralised Planning)		11
निर्देशात्मक नियोजन (Directional Planning), विकेन्द्रीकृत नियोजन (Decentralised Planning)		11
दीर्घावधिक नियोजन (Perspective Planning), अल्पकालीन नियोजन (Short Term Planning)		11
पंचवर्षीय योजना की समाप्ति	12	

5. भारत में बैंकिंग व्यवस्था36-64

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
भारत में बैंकिंग का इतिहास, भारतीय बैंकों की संरचना, अनुसूचित बैंक		12
गैर-अनुसूचित बैंक, अन्य विशेषीकृत बैंक		12
बैंकों का राष्ट्रीयकरण, महाविलय के बाद देश के 12 सरकारी बैंक		12
बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु समितियाँ एवं योजनाएँ		12
(Deflation), मुद्रा प्रत्यवस्फीति (Reflection)		12
पुनरावलोकन	12	

6. मुद्रा एवं पूँजी बाजार65-76

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
मुद्रा, साख मुद्रा (Credit Money)	12	
वैधानिक मुद्रा (Legal Currency, मुद्रा की पूर्ति (Supply of Money))	12	
मुद्रा की तरलता (Liquidity of Currency)	12	
मुद्रा की पूर्ति ज्ञात करना	12	
तरलता समुच्चय (Liquidity Aggregates), भारतीय वित्तीय व्यवस्था	12	
बीमा क्षेत्र में निजी कम्पनियों का प्रवेश, पुनरावलोकन	12	

7. भारतीय कृषि 77-102

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व		11
भारतीय कृषि की विशेषताएँ		11
कृषि से सम्बन्धित क्रान्तियाँ		11
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद		11

8. आधारभूत संरचना 103-127

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
भौतिक आधारभूत संरचना		11
ऊर्जा, परंपरागत स्रोत		11
कोयला खान विधेयक, 2015		11
ई-गवर्नेंस, शिक्षा		11
पुनरावलोकन		11

9. भारत में उद्योग एवं औद्योगिक नीति 128-163

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
भारत में औद्योगिक विकास	12	
बौद्धिक सम्पदा अधिकार	12	
महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	12	
आर्थिक गणना	12	

10. लोक वित्त एवं कर प्रणाली 164-189

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
लोक वित्त	12	
राजकोषीय नीति	12	
राजकोषीय नीति के उद्देश्य	12	
वित्त घाटे, भारत में बजट की परंपरा	12	
केन्द्रीय बजट के दस्तावेज	12	

11. जनांकिकी एवं भारत की जनगणना-2011 190-209

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
महत्वपूर्ण अवधारणाएँ, आयु संरचना	11	
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति - 2000	11	
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की सर्वोच्च प्राथमिकताएँ, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग	11	

12. भारत में निर्धनता एवं बेरोजगारी 210-220

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
निर्धनता के प्रकार	11	
सापेक्ष निर्धनता	11	
निरपेक्ष निर्धनता	11	
निर्धनता रेखा मापने के विविध फार्मूले	11	
एस. आर. हासिम समिति	11	

13. निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन 221-247

हेतु कार्यक्रम एवं कल्याणकारी योजनाएं

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
रोजगार कार्यक्रम एवं कौशल विकास योजना	11	11
मनरेगा योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	11	11
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन	11	11
एग्री उड़ान	11	11
स्वतांत्रोत्तर भारत में काल-क्रमानुसार महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं	11	11

14. विदेशी व्यापार एवं निवेश 248-266

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
विश्व व्यापार परिदृश्य		11
निर्यातों की पण्यवार रचना (प्रतिशत में शेयर द्वारा)		11
2011-12 और 2019-20 (अप्रैल-नवम्बर) में सबसे बड़े 10 निर्यात गनन्य		11
आयात का वस्तुवार संगठन (%) अंश अनुसार)		11
भारत का विदेश व्यापार : दिसम्बर, 2019		11

15. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान 267-276

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
विश्व बैंक		11
पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक		11
निवेश गारंटी एजेंसी, निवेश विवाद के निपटारे हेतु इंटरनेशनल सेंटर		11
भारत पर प्रभाव		11
एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक		11

16. महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली 277-286

Topic	NCERT Class Covered	
	Old	New
पुनरावलोकन		11

विगत वर्षों के प्रश्न (आईएएस मुख्य परीक्षा) 287-293

प्रैक्टिस प्रश्न (आईएएस एवं राज्य पीसीएस मुख्य परीक्षा हेतु) 294

2

भारतीय अर्थव्यवस्था : एक परिचय

प्रस्तावना

भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। इस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिल-जुलकर कार्य करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था संगठित एवं कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें उत्पादन एवं वितरण के माध्यम से विकास और संवृद्धि का निर्धारण होता है। भारत की अर्थव्यवस्था, वैश्वक अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान रखती है तथा यह देश के विकास परक कार्यों के सम्पादन तथा उत्पादन के लिए विभिन्न गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन कर निरंतर अग्रसर है।

वस्तुतः अर्थव्यवस्था किसी देश की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी ऐसी व्यवस्था होती है, जिसमें उस देश के समस्त उत्पादन, खपत, आय-व्यय इत्यादि सभी मदों का उल्लेख होता है।

अर्थशास्त्र की शाखाएँ

- अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है- **समष्टि अर्थशास्त्र** (Macro Economics) एवं **व्यष्टि अर्थशास्त्र** (Micro Economics)
- स्पेन्सर के अनुसार, समष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े-बड़े खण्डों से है। इसके तहत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिनका सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है; जैसे- मुद्रास्फीति की दर, राष्ट्र का कुल उत्पाद, बेरोजगारी का स्तर इत्यादि।
- समष्टि अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय आय, मुद्रा, रोजगार, सामान्य कीमत, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है।
- व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी आर्थिक इकाइयों से संबद्ध समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मांग, उत्पादन, कीमत निर्धारण मानव की आर्थिक आवश्यकताएं, उत्पाद को प्रेरित करने वाले तत्व तथा बाजार से उनके संबंध इत्यादि का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है।
- व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य बाजार में मांग और आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखना और उपभोग एवं मांग के अन्य तत्वों की पहचान रखना है।

विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण

विश्व बैंक का वर्गीकरण

- विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है, जिसका आधार प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होता है।

1. निम्न आयवाली अर्थव्यवस्था - 1135 \$ या कम
2. निम्न मध्य आयवर्ग की अर्थव्यवस्था - 1136-4465 \$
3. उच्च मध्य आयवर्ग की अर्थव्यवस्था - 4466-13845 \$
4. उच्च आयवर्ग की अर्थव्यवस्था- 13846 \$ या अधिक

इस वर्गीकरण के अनुसार अंगोला, जॉर्जिया और जॉर्डन को उच्च मध्य आय से हटाकर निम्न मध्य आय वर्ग; क्रोशिया एवं नौरू को उच्च आय वर्ग से उच्च-मध्य वर्ग; पलाऊ को उच्च-मध्य आय वर्ग से उच्च आय वर्ग; समोआ और टोंगा को निम्न मध्य वर्ग से हटाकर उच्च-मध्य वर्ग में शामिल किया गया है।

अर्थव्यवस्था के प्रकार

- प्रकृति, विस्तार, विकास के स्तर तथा विकास के तरीकों के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्न प्रकार हैं-
- **पूँजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था:** इस अर्थव्यवस्था में पूँजीपति वर्ग, पूँजी को ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में लगाता है, जिसमें उसे अधिक से अधिक लाभ हो सके। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि की अर्थव्यवस्थाएं पूँजीवादी हैं। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अत्यधिक प्रभावशाली होता है, इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है।
 - **समाजवादी अर्थव्यवस्था:** इस अर्थव्यवस्था में राज्य समस्त आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। भौतिक संसाधनों पर समाज एवं समुदाय का स्वामित्व होता है। इसमें बाजारी शक्तियाँ नियंत्रित रहती हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था इसका उदाहरण है।
 - **मिश्रित (Mixed) अर्थव्यवस्था:** इस अर्थव्यवस्था में पूँजीवादी तथा समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पायी जाती हैं। इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान (अर्थव्यवस्था में)

- होता है। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसे दोहरी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है।
- **खुली अर्थव्यवस्था:** यह अर्थव्यवस्था का ऐसा स्वरूप है, जिसमें पूँजीगत सेवाओं और वस्तुओं का बाह्य एवं अंतःप्रवाह दोनों अवाध गति से होते हैं तथा आयात एवं निर्यात का महत्वपूर्ण स्थान होता है; जैसे- हाँगकांग एवं सिंगापुर की अर्थव्यवस्था।
 - **बन्द अर्थव्यवस्था:** अर्थव्यवस्था के इस प्रकार में विदेशी व्यापार अर्थात् आयात-निर्यात पर प्रतिबंध होता है। इस अर्थव्यवस्था का बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है। उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था इसका प्रमुख उदाहरण है।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)

- प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है। इसमें कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियां शामिल की जाती हैं।
- कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्यन, खनन (उर्ध्वाधर खुदाई) एवं उत्खनन (क्षेत्रिज खुदाई) प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector)

- इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन को शामिल किया जाता है।
- निर्माण (जैसे भवन), विनिर्माण (किसी वस्तु का उत्पादन केन्द्र; जैसे सीमेंट, कपड़ा) तथा जलापूर्ति, गैस, विद्युत इत्यादि द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं।

तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)

- यह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएँ प्रदान करता है।
- बैंकिंग, बीमा, व्यापार, परिवहन एवं संचार, सामुदायिक सेवाएँ, भण्डारण इत्यादि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

चतुर्थक एवं पंचम क्षेत्र

- ➲ अर्थव्यवस्था के चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत बौद्धिक गतिविधियों यथा; संस्कृति, सरकार, शिक्षा, अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय इत्यादि को शामिल किया जाता है।
- ➲ पंचम क्षेत्र के अंतर्गत समाज या अर्थव्यवस्था में उच्चस्तरीय निर्णय लेनेवाले यथा; विज्ञान, विश्वविद्यालय, मीडिया इत्यादि को शामिल किया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण

- **कम प्रति व्यक्ति वास्तविक आय:** किसी भी देश की वास्तविक आय या राजस्व का अर्थ किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में एक इकाई के रूप में पूरे देश की क्रय शक्ति या क्रय शक्ति से है।

भारत सहित जो देश विकासशील हैं उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय विकसित देशों की तुलना में कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कम प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है।

➤ **प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता:** जब भारत जैसे विकासशील देशों में लोगों को नई नौकरी के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो लोगों को आय के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की ओर रुख करना पड़ता है। इन क्षेत्रों में वे व्यवसाय शामिल हैं जो लोग सदियों से करते आ रहे हैं जैसे कृषि, पशु प्रजनन आदि। ये क्षेत्र उन्हें उतना पैसा नहीं दिलाते जितना विकसित देशों के अन्य क्षेत्र इसलिए, प्राथमिक क्षेत्रों पर निर्भरता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई है।

➤ **जनांकिकीय लक्षण:** अधिक जनसंख्या घनत्व निम्न लिंगानुपात, औसत जीवन प्रत्याशा कम, शिशु मृत्युदर की अधिकता आदि भारतीय जनांकिकीय की विशेषताएँ हैं।

➤ **अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव:** 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 अरब है। इतनी बड़ी जनसंख्या के जीवन-स्तर को बनाए रखने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है।

➤ **पर्याप्त पूँजी का अभाव:** भारत में निम्न आय वर्ग वाली जनसंख्या की अधिकता है, अतः बचत दर कम है। इस कारण पूँजी निर्माण की दर भी कम है।

➤ **परिसम्पत्तियों का दोषपूर्ण वितरण:** परिसम्पत्तियों के वितरण में भारी असमानता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 51 प्रतिशत परिवारों का कुल परिसम्पत्ति में हिस्सा मात्र 10 प्रतिशत है, जबकि 9.6 प्रतिशत परिवारों के पास यह हिस्सा 49 प्रतिशत है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में 50.7 प्रतिशत परिवारों के पास मात्र 5.3 प्रतिशत तथा 14.2 प्रतिशत परिवारों के पास कुल परिसम्पत्ति का 66 प्रतिशत हिस्सा है।

➤ **बेरोजगारी की समस्या:** भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। यहाँ मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार की बेरोजगारी पायी जाती है। यहाँ बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण पूँजी का अभाव और कृषि में श्रम का नगण्य सीमान्त उत्पादन। कृषि में गुप्त या अदृश्य बेरोजगारी पायी जाती है। विकसित देशों में चक्रीय प्रकृति की बेरोजगारी पायी जाती है जो समर्थ मांग के अभाव में उत्पन्न होती है।

➤ **निम्न जीवन स्तर:** भारत में अधिकतर जनसंख्या को संतुलित भोजन प्राप्त नहीं होता। भोजन में कैलोरी तथा प्रोटीन की मात्रा निम्न है। विकसित देशों में औसत कैलोरी उपभोग 4,400 से भी अधिक है, वहीं भारत में यह थोड़ा अधिक हैं। चूंकि देश की 26 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे है, अतः संभव है कि उन्हें आवश्यक 2100 कैलोरी भी नहीं मिल पाती होगी।

➤ **निम्न स्तर की तकनीक:** विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ तकनीकी पिछड़ेपन से ग्रस्त होती हैं। भारत में एक ही उद्योग में नितांत अविकसित तकनीक के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है, किन्तु अधिकांश उत्पादन इकाइयों में घटिया तकनीक का प्रयोग होता है।

अल्पविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था में पूर्व-प्रचलित शब्द 'पिछड़े' और 'उन्नत' के स्थान पर 'अल्पविकसित' और 'विकसित' शब्दों का प्रयोग होने लगा। 'अल्पविकसित' शब्द 'पिछड़े' शब्द की अपेक्षा नरम शब्द है, क्योंकि इसमें विकास की संभावना पर बल दिया गया है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के प्रकाशनों में अल्पविकसित के स्थान पर 'विकासशील' शब्द का प्रयोग होने लगा है। 'विकासशील अर्थव्यवस्थाओं' से यह बोध होता है कि भले ही ये अर्थव्यवस्थाएँ अल्पविकसित हैं, किन्तु इनमें विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

आर्थिक संवृद्धि एवं विकास

आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth)

- किसी अर्थव्यवस्था में दी गयी समयावधि के अंतर्गत होनेवाली आर्थिक तथा वास्तविक आय को आर्थिक संवृद्धि कहा जाता है।
- यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ है कि आर्थिक संवृद्धि हो रही है।
- 1970 के दशक के बाद आर्थिक संवृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाने लगा है, इससे आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था। अब आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक विकास की पूर्व शर्त मानी जाने लगी है।
- आर्थिक संवृद्धि से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्रोतों में मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हो रही है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर को आर्थिक संवृद्धि दर कहा जाता है।

विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान

$$\text{आर्थिक संवृद्धि दर} = \frac{\text{वर्ष की NNP में परिवर्तन}}{\text{विगत वर्ष का NNP}} \times 100$$

आर्थिक संवृद्धि के संकेतक

- शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद,
- प्रतिव्यक्ति आय,
- जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक,
- क्रय शक्ति समता विधि,
- निवल आर्थिक कल्याण,
- मानव विकास सूचकांक,
- डेनिसन सूचकांक
- लिंग आधारित विकास सूचकांक

आर्थिक विकास (Economic Development)

- आर्थिक विकास एक व्यापक एवं गतिशील अवधारणा है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी प्रकार के विकास पर बल दिया जाता है।

पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध एक लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, जबकि अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा समता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है।

- आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप किसी देश की वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है, बर्तमान इसमें गरीबी-रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या और वितरण की असमानता न बढ़ने पाए।
- संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अनुसार, विकास मानवीय प्रयत्न का परिणाम है, आर्थिक विकास एक सतत् प्रक्रिया है, जिससे राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती रहती है।

सतत् (धारणीय) विकास की अवधारणा

आर्थिक विकास की परिभाषा में विगत् कुछ वर्षों से सतत् विकास (Subsustainable Development) पर जोर दिया जा रहा है। सतत् विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें उपलब्ध संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाता है कि वर्तमान जरूरतों के पूरा करने के साथ ही भावी पीढ़ी की जरूरतों में कटौती न होने पाए। सतत् विकास की अवधारणा का उद्य काटसन द्वारा लिखित पुस्तक 'द साइलेंट स्प्रिंग' 1962 में दिए गए विचारों को माना जाता है। 1980 ई. में दो भूवैज्ञानिकों- बाल फोअर तथा वेक जैकसन ने सतत् विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया।

- सकल घरेलू उत्पादन में परिवर्तन की दर को 'आर्थिक विकास दर' कहा जाता है।

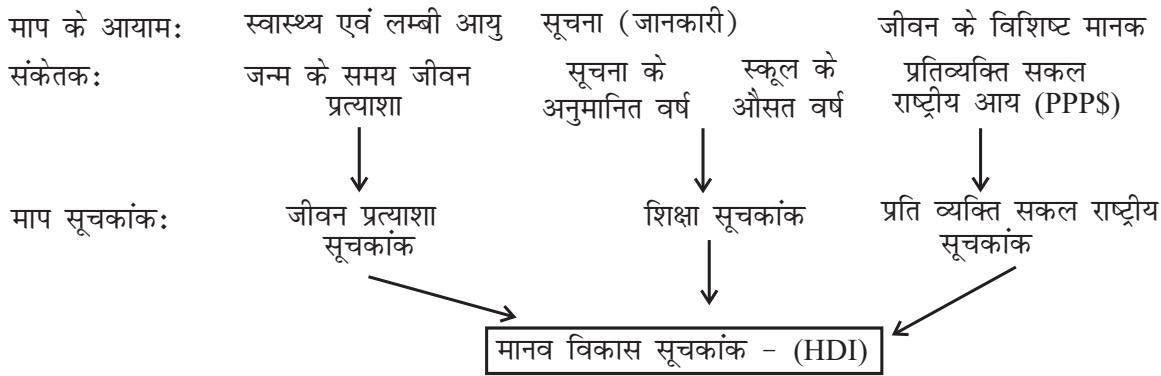
$$\text{आर्थिक विकास दर} = \frac{\text{वर्ष की GDP में परिवर्तन}}{\text{विगत वर्ष का GDP}} \times 100$$

आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक

मानव विकास सूचकांक (Human Development Index-HDI)

- 1990 ई. में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) से संबद्ध पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक तथा सहयोगी अर्थशास्त्री ए.के. सेन और सिंगर हंस ने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किया।
- यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के स्तर के आधार पर तैयार किया जाता है। यह यूएनडीपी का सूचकांक है, जिसका अधिकतम मूल्य '1' तथा न्यूनतम मूल्य '0' होता है।
- मानव विकास घटकों की रचना तीन सूचकांकों के आधार पर होती है-
 - (i) जीवन प्रत्याशा सूचकांक
 - (ii) शिक्षा सूचकांक
 - (iii) जीवन निर्वाह का स्तर, जिसमें क्रयशक्ति समायोजित प्रतिव्यक्ति आय डॉलर में व्यक्त करते हैं।

मानव विकास सूचकांक - (HDI)



- **सूचकांक का मापन:** अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश का मापन 0.896 एवं सबसे अधिक, मध्यम मानव विकास वाले देश का मापन 0.630 एवं इससे अधिक तथा निम्न मानव विकास वाले देश का मापन 0.505 एवं इससे अधिक होता है।

मानव विकास रिपोर्ट

मानव विकास रिपोर्ट लैंगिक असमानता, गरीबी और मानव विकास जैसे कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए अधिक व्यापक स्टैड-इन के रूप में अतिरिक्त समग्र सूचकांक प्रदान करती है। मानव विकास, या मानव विकास दृष्टिकोण, केवल उस अर्थव्यवस्था की समृद्धि के बजाय मानव जीवन की समृद्धि को बढ़ाने से संबंधित है जिसमें मनुष्य रहते हैं।

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

(Multi-dimensional Poverty Index - MPI)

- यह सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर में व्यक्तिगत स्तर पर बहुआयामी कठिनाइयों की पहचान करता है। इसके लिए परिवारों के सर्वेक्षण से प्राप्त सूक्ष्म आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है।
- सर्वेक्षण में शामिल परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का वर्गीकरण 'गरीब' और 'गरीब नहीं' के रूप में किया जाता है तथा आंकड़ों का समायोजन कर गरीबों के राष्ट्रीय मानक की पहचान की जाती है।
- बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जनसंख्या के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जो बहुआयामी निर्धनता का शिकार है और जिसने तीव्रता और सघनता के साथ उस कठिनाई को अनुभव किया है।
- यूएनडीपी के सहयोग से 'ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल द्वारा विकसित यह सूचकांक HDI के तीनों आयामों (शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर) के संदर्भ में 10 वंचनों पर आधारित है।

10 वंचनाएँ

● शिक्षा

1. यदि परिवार के किसी सदस्य ने 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की है।
2. यदि कोई स्कूल आयु का छात्र (कक्षा 1-8 तक) स्कूल नहीं जा रहा है।
3. यदि परिवार के किसी बच्चे की मृत्यु होती है।
4. यदि कोई बच्चा या वयस्क कुपोषित है।
5. यदि परिवार को विद्युत उपलब्ध नहीं है।
6. स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता, यदि वह 30 मिनट की पैदल दूरी से अधिक है।
7. यदि परिवार के पास उचित शौचालय नहीं है या साझे में है।
8. यदि फर्श गन्दा या कच्चा है।
9. यदि परिवार लकड़ी, चारकोल या गोबर जैसे मलीन ईंधन से खाना पकाता है।
10. यदि परिवार के पास संचार परिसंपत्ति (रेडियो, टेलीफोन, टीवी), परिवहन परिसंपत्ति (किसी प्रकार के यातायात साधन) या जीविका से जुड़ी परिसम्पत्ति (कृषि योग्य भूमि, रेफ्रीजरेटर, मवेशी आदि) नहीं है।

- 10 वंचन संकेतकों के आधार पर एक व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा, यदि वह इनमें से कम-से-कम एक-तिहाई (33.33 प्रतिशत) भारित संकेतकों पर वर्चित है। कोई व्यक्ति जितने अधिक संकेतकों के संदर्भ में वर्चित होगा, उसकी निर्धनता प्रबलता भी उतनी ही अधिक होगी।

$$\text{MPI} = \frac{\text{बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों का प्रतिशत}}{\text{बहुआयामी निर्धनता की औसत प्रबलता}}$$

असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक (IHDI)

- 'असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक' (Inequality adjusted HDI-IHDI) का सर्वप्रथम प्रकाशन मानव विकास रिपोर्ट, 2010 में किया गया था।

- यह सूचकांक विषम समाज में लोगों के विकास स्तर को मापता है। पूर्ण समान समाज की स्थिति में HDI और IHDI के मान बराबर होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय के विभिन्न आयामों में असमानता की स्थिति होने पर IHDI औसत HDI से कम होगा अर्थात् IHDI के HDI से कम होने की स्थिति समाज में असमानता को प्रदर्शित करती है।
- IHDI हेतु आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं के मापन के लिए ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंथनी बार्नेस एटकिंसन (Anthony Barnes Atkinson) द्वारा विकसित प्रविधि का प्रयोग किया जाता है।

लैंगिक अंतराल सूचकांक

- वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है।
- लैंगिक अंतराल असमानता का तात्पर्य “लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेद-भाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है जिससे वे समाज में शोषण, अपमान और भेद-भाव से पीड़ित होती हैं।”
- वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक निम्नलिखित चार क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है:
 - आर्थिक भागीदारी और अवसर (Economic Participation and Opportunity)
 - शैक्षिक अवसर (Educational Attainment)
 - स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता (Health and Survival)
 - राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी (Political Empowerment)
- यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है।
- इसमें 0 का अर्थ पूर्ण लिंग असमानता तथा 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता है।
- पहली बार लैंगिक अंतराल सूचकांक वर्ष 2006 में जारी किया गया था।

सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता (Gross National Happiness, GNH)

- सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता देश की गुणवत्ता को समग्र तरीके से मापता है। इसके अंतर्गत ऐसा विश्वास किया जाता है कि मानव समाज का विकास तब होता है, जब भौतिक और आध्यात्मिक विकास साथ-साथ होते हैं और वे एक-दूसरे के पूरक होते हैं।
- इस सूचकांक की अवधारणा भूटान के नरेश जिम्मे सिंग्मे वांगचुक ने 1972ई. में दी थी। इसे मापने के लिए सात संकेतकों पर विचार किया जाता है- (i) शारीरिक (ii) मानसिक (iii) अच्छा शासन (iv) पारिस्थितिक जीवन शक्ति (v) सामाजिक (vi) आर्थिक (vii) कार्य स्थल।

हैप्पी प्लैनेट इण्डेक्स (Happy Planet Index, HPI)

- न्यू इकोनॉमिक्स फाउण्डेशन के द्वारा किए जाने वाले इस सूचकांक के अंतर्गत यह माना गया है कि आर्थिक विकास का मापक प्रतिव्यक्ति आय को नहीं, बल्कि स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन को माना जाना चाहिए।

- इस सूचकांक का उद्देश्य यह बताना नहीं है कि विश्व में सबसे खुशहाल देश कौन-सा है, बल्कि यह उस सापेक्षिक कुशलता को प्रदर्शित करता है, जिससे कोई देश पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का उपभोग अपने नागरिकों के जीवन को स्वस्थ तथा खुशहाल जीवन में परिवर्तन करने के लिए करता है।
- इस सूचकांक का आधार जीवन संतुष्टि, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा पारिस्थितिकी की स्थिति है।

$$\text{हैप्पी प्लैनेट इण्डेक्स} = \frac{\text{संतुलित जीवन} \times \text{जीवन प्रत्याशा}}{\text{पारिस्थितिकी}}$$

विश्व खुशहाली सूचकांक

वर्ल्ड हैप्पीनेस इण्डेक्स के अनुसार, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट समग्र खुशहाली का एक पैमाना है। रैंकिंग उत्तरदाताओं के अपने व्यक्तिगत जीवन के मूल्यांकन की रिपोर्ट पर आधारित है, और वे राष्ट्रीय खुशहाली पर लेखों को भी ध्यान में रखते हैं।

विश्व खुशहाली सूचकांक निर्धारित करने के लिए कारक

- दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची संकलित करने और ग्रह पर हर देश को रेट करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क कुल छह तत्वों को ध्यान में रखता है। पैरामीटर निम्नलिखित हैं:
- डायस्टोपिया अन्याय से पीड़ित होने, अधिनायकवाद के हमले के तहत, या सर्वनाश के बाद की दुनिया में होने के अनुभव को दर्शाता है।
- नागरिकों की धारणा कि भ्रष्टाचार को उन्होंने किस तरह महसूस किया है, भ्रष्टाचार की उनकी धारणा कहा जाता है।
- उदारता सहानुभूति की भावना के साथ व्यक्तियों के बीच मौलिक मानवीय संबंध है।
- जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता। यह पहलू उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें कोई सामाजिक नतीजों के कारण समझौता किए बिना जीवन में निर्णय और विकल्प बनाने के लिए पर्याप्त रूप से मुक्त या स्वतंत्र होता है।
- घातक रोगों या पीड़िओं से मुक्त एक स्वस्थ जीवन की अपेक्षा को “स्वस्थ जीवन प्रत्याशा” के रूप में जाना जाता है।
- सामाजिक समर्थन इस बात का संकेतक है कि किसी देश के निवासी एक दूसरे से कितना समर्थन प्रदान करते हैं और प्राप्त करते हैं।
- अपनी आबादी द्वारा विभाजित राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का भी गरीबी और वित्तीय सुरक्षा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI)

- ‘वैश्विक भुखमरी सूचकांक’ को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी ‘कंसर्न वर्ल्डवाइड’ (Concern Worldwide) और जर्मनी के एक संगठन ‘वेल्ट हंगर हिल्फे’ (Welt Hunger Hilfe) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।

- GHI स्कोर, चार घटक संकेतकों के आधार पर निकाला जाता है:
 1. अल्पपोषण
 2. चाइल्ड वेस्टिंग
 3. चाइल्ड स्टर्टिंग
 4. बाल मृत्यु दर
- इन चार संकेतकों के मूल्यों के आधार पर 0 से 100 तक के पैमाने पर भुखमरी को निर्धारित किया जाता है जहाँ 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर (भूख नहीं) है और 100 सबसे खराब है।
- प्रत्येक देश के GHI स्कोर को निम्न से अत्यंत खतरनाक स्थिति के रूप वर्गीकृत किया जाता है।

GHI गंभीरता स्केल (GHI Severity Scale)

कम (Low)	मध्यम (Moderate)	गंभीर (Serious)	खतरनाक (Alarming)	बेहद चिंताजनक (Extremely Alarming)
≤ 9.9	10.0–19.9	20.0–34.9	35.0–49.9	≥ 50.0

- GHI-2020 में भारत के प्रदर्शन को देखते हुए मौजूदा कुपोषण स्थिति में सुधार की दिशा में किये जा रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है। गैरतलब है कि भारत ने वर्ष 2022 तक 'कुपोषण मुक्त भारत' के लिये एक कार्ययोजना विकसित की है। वर्तमान रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस योजना में अपेक्षित सुधार किया जाना चाहिये।

सतत् विकास लक्ष्य (एजेण्डा 2030)

- 2030 ई. तक भूख और गरीबी को समाप्त करने, लिंग समानता को सुनिश्चित करने तथा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 193 सदस्य देशों द्वारा पूर्व में लागू किया गया।
- एजेंडा 2030 में 17 मुख्य लक्ष्यों और 169 सहायक लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए '5P' (People, Plannet, Peace, Prosperity, Partnership) पर जोर दिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि 2000-2015 तक की अवधि के लिए सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की योजना बनायी गयी थी।
- भारत ने लक्षित लक्ष्यों में से एचआईवी/एडस, गरीबी, सार्वभौमिक शिक्षा तथा शिशु 'मृत्यु दर में निर्धारित मानकों को 2015 ई. तक प्राप्त कर लिया है, किन्तु अन्य लक्ष्यों में भारत अभी बहुत पीछे है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को एजेण्डा 2030 ई. में निहित लक्ष्यों के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।
- 'ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड' 2030 एजेंडा फॉर स्टेनेबल डेवलपमेंट', जिसे 'सतत् विकास लक्ष्य' भी कहा गया है, जो 2016-30 की अवधि तक प्राप्त करना है। इस एजेंडा में निर्धारित 17 प्रमुख लक्ष्यों में से लक्ष्य सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों से लिए गए हैं।

एजेण्डा 2030 के 17 लक्ष्य

1. गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति।
 2. भूख समाप्ति, खाद्य और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
 3. सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
 4. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
 5. लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
 6. सभी के लिये स्वच्छता और पानी के सतत् प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
 7. सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।
 8. सभी के लिये निरंतर समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, और सभ्य काम को बढ़ावा देना।
 9. लचीली बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत् औद्योगीकरण को बढ़ावा।
 10. देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
 11. सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।
 12. स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
 13. जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई करना।
 14. स्थायी सतत् विकास के लिये महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
 15. सतत् उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय परिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
 16. सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके।
 17. सतत् विकास के लिये वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना।
- इन लक्ष्यों का उद्देश्य विकास के अपूर्ण कार्य को पूरा करना तथा ऐसे विश्व की संकल्पना को मूर्तरूप देना है, जिसमें चुनौतियां कम तथा आशाएँ अधिक हों।
- सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम- मेक इंडिया, बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (शहरी एवं ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्कूल इंडिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इत्यादि सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
- केंद्र सरकार ने सतत् विकास के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने तथा इसके समन्वय की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी है। राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकार ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा के लिए नागरिक समाज से भी सुझाव मांगे हैं।

- भारत को यदि एजेंडा 2030 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जो सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित नीतियों से समर्जन्स्य स्थापित करती हो।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट

- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट, जिसे पहले एसडीजी सूचकांक के रूप में जाना जाता था, सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के संबंध में सभी देशों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक अनूठा वैश्विक अध्ययन है। एसडीजी, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों - एसडीजी सूचकांक के पूर्ववर्तियों के विपरीत, न केवल विकासशील देशों के लिए बल्कि औद्योगिक देशों के लिए भी स्थायी लक्ष्य निर्धारित करता है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य वर्ष 2030 तक इस विश्व को गरीबी, बीमारी और भूख से मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमत हुए हैं।
- लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक राष्ट्र के शासी निकाय सतत विकास और विकास के लिए एसडीजी सूचकांक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न नियमों को लागू करते हैं।

एसडीजी सूचकांक में देशों की रैंकिंग कैसी है?

सतत विकास रिपोर्ट की गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों द्वारा निर्धारित सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों और 169 लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश की प्रगति के अनुसार की जाती है। 100 अधिकतम प्राप्त स्कोर है, और सभी देशों को प्राप्त सर्वोत्तम परिणामों के अनुसार रैंक किया गया है।

हरित अर्थव्यवस्था एवं ग्रीन जी.एन.पी.

- **हरित अर्थव्यवस्था:** अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप, जिसमें पर्यावरण जोखिमों एवं पारिस्थितिकी नुकसान को कम करते हुए उत्पादन एवं विकास पर ध्यान दिया जाता है, हरित अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसका लक्ष्य पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना सतत विकास करना है।
- **ग्रीन जी.एन.पी.:** किसी दी हुई समयावधि में उत्पादित की जाने वाली समस्त जी.एन.पी. जो पर्यावरण के सम्पूर्ण मानकों को ध्यान में रखते हुए उत्पादित की गयी है, ग्रीन जी.एन.पी कहलाती है। इसकी शुरुआत 1995 ई. से की गयी थी।

पुनरावलोकन

- ⌚ विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है।
- ⌚ मिश्रित अर्थव्यवस्था को 'दोहरी अर्थव्यवस्था' भी कहा जाता है।
- ⌚ 1970 के दशक के बाद आर्थिक संस्कृति और आर्थिक विकास को अलग-अलग देखा जाने लगा।
- ⌚ बाल फोअर और वेक जैकसन ने वर्ष 1980 में सतत विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया।
- ⌚ वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट में तीन नए सूचकांक-असमानता प्रभाव, लिंग असमानता तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक शामिल किए गए हैं।
- ⌚ वर्ष 2007 और 2008 की मानव विकास रिपोर्ट को संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया था।
- ⌚ राष्ट्रीय सकल प्रसन्नता सूचकांक की अवधारणा भूटान नरेश जिग्मे सिंग्मे बांगचुक ने 1972 ई. में दी थी।
- ⌚ एजेंडा 2030 में 17 मुख्य लक्ष्य तथा 169 सहायक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

अभ्यास प्रश्न-1

1. किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है-
 - (a) गरीबी के अनुपात से
 - (b) प्रति व्यक्ति आय से
 - (c) राष्ट्रीय आय से
 - (d) बेरोजगारी की दर से
2. निम्न में से कौन-सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है?
 - (a) वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
 - (b) वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि।
 - (c) किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
 - (d) जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
3. मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है-
 - (a) जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है।
 - (b) जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो।
 - (c) जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो।
 - (d) जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की सामान भागीदारी हो।

4. भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है-
- वृहद् एवं कुटीर उद्योग का सह-अस्तित्व
 - आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग
 - सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं
5. भारत की अर्थव्यवस्था है-
- उदारवादी अर्थव्यवस्था
 - समाजवादी अर्थव्यवस्था
 - मिश्रित अर्थव्यवस्था
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं
6. फ्रांस की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है?
- | | |
|--------------|---------------|
| (a) समाजवादी | (b) पूँजीवादी |
| (c) मिश्रित | (d) खुली |
7. उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था है-
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| (a) बंद अर्थव्यवस्था | (b) खुली अर्थव्यवस्था |
| (c) मिश्रित अर्थव्यवस्था | (d) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था |
8. कृषि-वानिकी अर्थव्यवस्था का कौनसा क्षेत्र है?
- | | |
|--------------|-----------------------|
| (a) द्वितीयक | (b) प्राथमिक |
| (c) तृतीयक | (d) इनमें से कोई नहीं |
9. बाल फोअर तथा वेक जैक्सन ने कब सतत विकास की अवधारण को प्रतिपादित किया?
- | | |
|----------------|----------------|
| (a) 1978 ई में | (b) 1981 ई में |
| (c) 1982 ई में | (d) 1980 ई में |
10. पाकिस्तान के किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया?
- | | |
|-----------------|-------------------|
| (a) महबूब-उल-हक | (b) मसूद अहमद |
| (c) अहमद फारूकी | (d) मुहम्मद उज़ेर |
11. मानव विकास रिपोर्ट में द्वितीय स्थान पर कौनसा देश है?
- | | |
|------------|-----------------|
| (a) नार्वे | (b) आस्ट्रेलिया |
| (c) जर्मनी | (d) डेनमार्क |
12. सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा किस देश के नरेश ने दी?
- | | |
|-------------|----------------|
| (a) ब्रिटेन | (b) नेपाल |
| (c) भूटान | (d) इंडोनेशिया |
13. वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2017 में भारत का स्कोर है-
- | | |
|----------|----------|
| (a) 30.2 | (b) 30.5 |
| (c) 31.4 | (d) 32.5 |
14. सतत विकास सूचकांक में भारत को कौनसा स्थान प्राप्त है?
- | | |
|-------------|-------------|
| (a) 116 वाँ | (b) 115 वाँ |
| (c) 114 वाँ | (d) 113 वाँ |
15. विश्व बैंक द्वारा प्रति वर्ष किस महीने में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करता है?
- | | |
|-----------|-------------|
| (a) जून | (b) जुलाई |
| (c) अगस्त | (d) सितम्बर |
16. मानव विकास सूचकांक के अन्तर्गत आता है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा *[IAS Prelims 1997]*
- | |
|---|
| (a) यू.एस. डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन |
| (b) वास्तविक क्रयशक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन |
| (c) यू.एस. डॉलरों में सकल राष्ट्रीय उत्पादन |
| (d) यू.एस. डॉलरों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय |
17. विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्थाएँ (Low Income Economies) वे हैं, जिनके लिए 1994 में प्रति व्यक्ति GNP थी— *[IAS Prelims 1998]*
- | |
|---------------------|
| (a) US \$ 925 या कम |
| (b) US \$ 825 या कम |
| (c) US \$ 725 या कम |
| (d) US \$ 525 या कम |
18. मानव निर्धनता सूचक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? *[IAS Prelims 1998]*
- | | |
|----------|----------|
| (a) 1994 | (b) 1995 |
| (c) 1996 | (d) 1997 |
19. प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य सेन से दिल्ली में विमोचन कराया, वह है *[IAS Prelims 1999]*
- | | |
|------------------|-------------------|
| (a) पश्चिम बंगाल | (b) केरल |
| (c) मध्य प्रदेश | (d) आन्ध्र प्रदेश |
20. एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय (Y) है (C, I, G, X, M का क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात) *[IAS Prelims 2000]*
- | |
|-------------------------------|
| (a) $Y = C + I + G + X$ |
| (b) $Y = I + G - X + M$ |
| (c) $Y = C + I - G + (X - M)$ |
| (d) $Y = C + I - G + (X - M)$ |
21. भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गाँव (Sample village) के लिए नहीं देता है *[IAS Prelims 2000]*
- | |
|--|
| (a) आधारित संरचना एवं सुख साधन सूचकांक |
| (b) शिक्षा सम्बन्धित सूचकांक |
| (c) स्वास्थ्य सम्बन्धित सूचकांक |
| (d) बेरोजगारी सम्बन्धित सूचकांक |
22. मानव विकास की बात करें तो एशियाई देशों में सर्वोत्तम निष्पादन (Best Performance) है *[IAS Prelims 2000]*
- | | |
|---------------|------------------|
| (a) चीन का | (b) मलेशिया का |
| (c) कोरिया का | (d) फिलीपीन्स का |
23. किसी देश की आर्थिक संवृद्धि का सबसे उपर्युक्त मापदण्ड है, उसका *[IAS Prelims 2001]*
- | |
|-------------------------------|
| (a) सकल घरेलू उत्पाद |
| (b) निवल घरेलू उत्पाद |
| (c) निवल राष्ट्रीय उत्पाद |
| (d) प्रति व्यक्ति वास्तविक आय |
24. निम्नलिखित में से कौन-से मानव विकास के चार स्तंभ माने जाते हैं? *[CDS 2020-I]*
- | |
|--|
| (a) साम्या (निष्पक्षता), समावेशन, उत्पादकता और सशक्तिकरण |
| (b) साम्या, उत्पादकता, सशक्तिकरण और धारणीयता (स्थिरता) |
| (c) उत्पादकता, लिंग, समावेशन और साम्या |
| (d) श्रम, उत्पादकता, समावेशन और साम्या |

25. टी. माल्थस ने 'दी माल्थूसियन थ्योरी' नामक प्रसिद्ध सिद्धान्त को प्रतिपादित किया, जो सम्बन्धित है *[UPPCS 2022]*
- निर्धनता से
 - जनसंख्या से
 - बेरोजगारी से
 - अर्थव्यवस्था से
26. निम्नलिखित में से कौन-सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है?
- पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार *[UPPCS 2021]*
 - जनसंख्या में परिवर्तन
 - विशेषीकृत क्रियाओं/गतिविधियों में श्रम विभाजन
 - तकनीकविद एवं नौकरशाह

अभ्यास प्रश्न-2

1. भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है-
- कृषि की प्रधानता
 - उद्योग की प्रधानता
 - न्यून प्रति व्यक्ति आय
 - वृहद् बेरोजगारी
- नीचे लिखे कूट से सही उत्तर चुनिए:
- 1 या 2 केवल
 - 1, 2 व 3 केवल
 - 2, 3 व 4 केवल
 - 1, 3 व IV केवल
2. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- विगत् पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत् रूप से बढ़ी है।
 - विगत् पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत् रूप से बढ़ी है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1 और न ही 2
3. निम्न कथनों पर विचार कीजिए— *[IAS Prelims 2003]*
- भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क
- राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है।
 - का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है।
- इन कथनों में से कौन-सा/से सही है/ हैं ?
- केवल 1
 - केवल 2
 - दोनों 1 और 2
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं
4. नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है *[IAS Prelims 1997]*
- कथन (A) :** आर्थिक सार्वभौमवाद के प्रादुर्भाव का यह अर्थ नहीं है कि समाजवादी विचारधारा का पतन हो जाए।
- कथन (R) :** समाजवादी विचारधारा विश्ववाद और सार्वभौमवाद में विश्वास करती है।
- ऊपर के दोनों वक्तव्यों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
- A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है
 - A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
 - A सही है परन्तु R गलत है
 - A गलत है परन्तु R सही है
5. निम्नलिखित में कौन-कौन-से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक (रियल सेक्टर) का निर्माण करते हैं?
- किसानों का अपनी फ़सलें काटना *[UPSC 2022]*
 - कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना
 - किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना।
- किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रूपया-अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना
- नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
- केवल 1 और 2
 - केवल 2, 3 और 4
 - केवल 1, 3 और 4
 - 1, 2, 3 और 4

व्याख्या सहित समाधान

उत्तरमाला-1

- (b)
- (b)
- (b)
- (c)
- (c)
- (b)
- (a)
- (b)
- (d)
- (a)
- (b)
- (c)
- (c)
- (a)
- (b)
- (d)
- मानव विकास सूचकांक किसी देश के रहन-सहन के स्तर को दिखाता है। इसमें शिक्षा का स्तर, वास्तविक आय और

जीवन की अवधि सम्मिलित होते हैं। 1990 में महबूब उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक बनाया था।

- (c) WDR (World Development Report) वैश्विक विकास रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष बर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। 1994 की रिपोर्ट के अनुसार जिस अर्थव्यवस्था में प्रतिव्यक्ति आय 725 या उससे कम अमेरिका डॉलर थी, उसे निम्न आय अर्थव्यवस्था कहा गया है।

18. (d) सर्वप्रथम मानव गरीबी के सूचकांक के आधार 1997 ई० में मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इनमें तीन सिद्धांतों को अपनाया गया था।
 (i) स्वास्थ्य सेवाएँ
 (ii) सुरक्षित पेयजल एवं पर्याप्त भोजन
 (iii) कम उम्र में मौत का जोखिम
19. (c) मध्य प्रदेश पहला राज्य था, जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार कर 1995 में प्रो. अर्मत्य सेन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का विमोचन करवाया।
20. (c) किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समयावधि में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) कहा जाता है। अतः GNP में देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को भी सम्मिलित किया जाता है, अतः $GNP = [C + I + G + (X - M)]$
21. (d) राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा सरकार देश में मानव विकास के क्षेत्र की स्थिति दर्शाती है। इस रिपोर्ट में मानव विकास के क्षेत्र में हुये परिवर्तनों से हमें अवगत कराया जाता है। रिपोर्ट में आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में प्रगति का आंकलन किया जाता है। रिपोर्ट में सरकारी नीतियों का, जो मानव विकास से सम्बन्धित है, भी आंकलन होता है। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के स्तर पर आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं जो मानव विकास की स्थिति को दर्शाते हैं। इसमें आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, जनसंख्यकीय, सामाजिक सुविधायें, शासन प्रणाली और अपराध से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण 1980 में स्थापित मापदंडों के अनुसार किया जाता है। इन आंकड़ों पर लगातार नज़र रखी जाती है। मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक बनाये जाते हैं। इनको बनाने की प्रक्रिया में भारत में पाये गये सामाजिक और आर्थिक कारकों को देखते हुये परिवर्तन किया गया है।
22. (c) मानव विकास जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा की दर पर निर्भर करता है। रहन-सहन का स्तर भी बहुत महत्वपूर्ण है। एशिया के देशों में कोरिया का स्थान मानव विकास तालिका में सबसे ऊपर आता है। कोरिया में शिशु मृत्यु दर केवल 6 प्रति हज़ार है, जबकि साक्षरता की दर 98% है।
23. (d) प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय का दूसरा अर्थ कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय है। दूसरे शब्दों में सभी घटकों की आय जोड़ने से राष्ट्रीय आय बनती है।
24. (b) मानव विकास के लिए चार प्रमुख स्तम्भ-
- (1) साम्य (Equity)- इसके तहत देश के सभी नागरिकों को काम के समान अवसर दिये जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
 - (2) उत्पादकता (Productivity)- यहां उत्पादकता का मतलब है कि समाज के मानवीय मजदूरी उत्पादकता या मानवीय कार्य उत्पादकता समाज में धनी और गरीब लोगों के बीच भेद नहीं होना चाहिए। धनी व्यक्तियों को समाज के गरीब लोगों की स्वास्थ्य सुविधायें और सुरक्षा आदि में सहयोग करना चाहिए।
 - (3) सशक्तिकरण (Empowerment)- देश में लोगों को अधिक स्वतन्त्रता व आयाम देना चाहिए। देश में सुशासन होना चाहिए और नीतियाँ लोगों पर आधारित होनी चाहिए।
 - (4) धारणीयता (Sustainable)- देश में अवसरों की स्थिरता होनी चाहिए। सभी के लिए सभी वातावरण में समान अवसर होने चाहिए।
25. (b) 26. (d)
- ### उत्तरमाला-2
-
1. (d) 2. (d)
3. (d) स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा लगाया हुआ एक ऐसा कर है, जिसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर लगाया जाता है। केन्द्रीय सरकार इस कर को लागू करती है पर सारी आय राज्य सरकार को जाती है। भारतीय संविधान के सातवें अनुसूची में स्टाम्प शुल्क है। केन्द्र की सूची में इसका स्थान 91वां है। राज्यों की सूची में इसका स्थान 63वां है।
4. (a) वैश्वीकरण एक ऐसी नीति है जिसमें देश के हित की जगह विश्व का हित सर्वोपरि है। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक पद्धति है जहां उत्पादन के समस्त साधन सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं और सामाजिक संतुष्टि बढ़ाने के लिये उपयोग में लाये जाते हैं। सर्वहितवाद (Universalism) का अर्थ है कि कुछ सिद्धांतों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पालन हो।
5. (a)